

## ज़िला-स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान

### प्रलिमिस के लिये:

सकल घरेलू उत्पाद, ज़िला घरेलू उत्पाद, भारतीय अरथव्यवस्था के क्षेत्र, सकल वरदधति मूलय

### मेन्स के लिये:

भारत में GDP अनुमान और सीमाएँ, भारत की आरथकी नीतियाँ

सरोत: बज़िनेस लाइन

### चर्चा में क्यों?

भारत की आरथकी वृद्धिका आकलन लंबे समय से राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुमानों के माध्यम से किया जाता रहा है, जिससे आरथकी आकलन में ज़िलों {ज़िला घरेलू उत्पाद (DDP) अनुमान} की अनदेखी होती रही है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तथ्य पर बल दिया कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अरथव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भारत को ज़िलावार योगदान निधारित करना होगा और स्थानीय विकास रणनीतियों का क्रियान्वन करना होगा।

### वर्तमान की GDP अनुमान पद्धतिक्रिया है?

- वर्तमान की GDP अनुमान पद्धति:** भारत के GDP का अनुमान क्षेत्र के आधार पर ऊर्धवाधर और अधरोर्धव दृष्टिकोण के मशिरण का उपयोग कर लगाया जाता है।
  - प्राथमिक क्षेत्र** (कृषि, वानकी, मत्स्यन और खनन) के अंतर्गत अधरोर्धव दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, जिसमें ज़िला स्तर से ऊपर की ओर डेटा एकत्र किया जाता है।
  - द्वितीयक** (वनिरिमाण, निरिमाण) और **तृतीयक** (सेवाएँ, व्यापार, बैंकगी) क्षेत्र में ऊर्धवाधर दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय GDP को ज़िला स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से आरथकी गतिविधियों को मापने के बजाय रोज़गार के स्तर और बुनियादी ढाँचे की उपस्थिति जैसे संकेतकों के आधार पर राज्यों और ज़िलों में विभाजित किया जाता है।
- सीमाएँ:** वर्तमान GDP अनुमान पद्धतियों से स्थानीय क्षेत्रीय शक्तियों, विशेष रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की अनदेखी होती है।
  - एक ही राज्य के भीतर भी ज़िलों में आरथकी वृद्धि स्तर अलग-अलग होती है, लेकिन विस्तृत डेटा के अभाव से सामान्य नीतियाँ बनाई जाती हैं।
    - इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविक समय की गतिविधियों की उपेक्षा होती है, जिससे अशुद्धियाँ होती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र {अवैतनिक शरम (विशेष रूप से महिलाएँ)} के डेटा अभाव के कारण GDP अनुमान सटीक नहीं रहता है।
  - स्टेट ऑफ वर्कगी इंडिया (SWI 2023)** रपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर GDP वृद्धि और रोज़गार के बीच संबंध अदृढ़ है, और ज़िला स्तर पर यह मुद्दा और भी अधिक गंभीर है।
    - रोज़गार संबंध GDP डेटा के अभाव में, विकास नीतियों में रोज़गार सृजन और सामाजिक समानता के बजाय केवल आरथकी उत्पादन को ही महत्ता दिये जाने की संभावना रहती है।

### क्षेत्र स्टडी

- कोवडि-19 के दौरान, सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने एक समान GDP वितरण लागू किया, जिससे वसिंगतियाँ हुईं।
  - उत्तर प्रदेश (UP) ने अपने अनुमानति **सकल राज्य वरदधति मूलय (GSVA)** में गंभीर त्रुटियों का हवाला देते हुए आपत्ति व्यक्त की। कृषि से 25% GSVA और संबंध क्षेत्र में 65% कार्यबल के साथ, राज्य ने तरक दिया कि औद्योगिक राज्यों की तुलना में इसकी अरथव्यवस्था कम प्रभावित हुई है।

- वन-साइज़-फटिस-ऑल दृष्टिकोण के कारण UP की GDP गणित की अतरिजना हुई, जिससे सटीकता के लिये अधरोरध्व, ज़िला-स्तरीय जीडीपी अनुमान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

# GDP और उससे संबंधित पद



## सकल घरेलू उत्पाद (GDP):

- एक वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं/सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य
- GDP की गणना करने के 3 तरीके - व्यय, उत्पादन, आय विधि
- यह किसी देश की अर्थव्यवस्था/विकास दर का अनुमान लगाने के लिये एक आर्थिक स्ट्रीप्शॉर्ट प्रदान करता है
- GDP किसी देश के समग्र जीवन स्तर/कल्याण की सटीक माप नहीं है
- $GDP = \text{उपभोग की वैर्ष वस्तुएँ} + \text{आय सेवाएँ (C)} + \text{निवेश (I)} + \text{सरकारी व्यय (G)} + (\text{निर्यात (X)} - \text{आयात (M)})$

### नामात्र GDP (NGDP)

- मौजूदा कीमतों पर GDP
- इसमें मुद्रास्फीति/बढ़ती कीमतें शामिल हैं
- इसे उत्पादन की विभिन्न तिमाहियों (एक ही वर्ष में) की तुलना करने के लिये उपयोग किया जाता है

$$\text{GDP मूल्य अवस्थितिकारक} = (NGDP \div RGDP) * 100$$

**उदाहरण:** एक ऐसे देश पर विचार करते हैं जो केवल ब्रेड का उत्पादन करता है

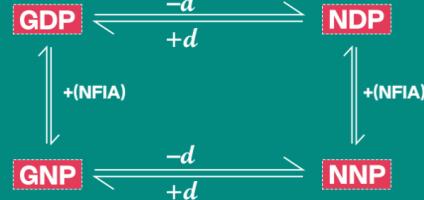
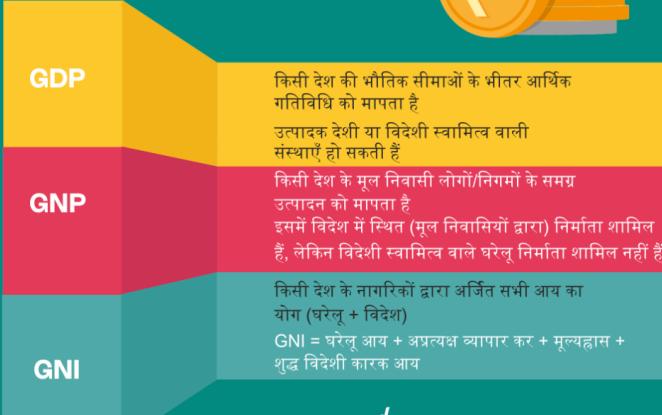
**वर्ष 2021:** इसने 10 रुपये (प्रति) की कीमत पर 100 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया अतः वर्तमान मूल्य पर GDP = 1000 रुपये

**वर्ष 2022:** इसने 15 रुपये (प्रति) की कीमत पर 110 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया अतः वर्तमान मूल्य पर GDP = 1650 रुपये

वर्ष 2022 के लिये  $RGDP$  (आधार वर्ष - 2021) =  $110 \times 10$  रुपये = 1,100 रुपये यहाँ  $GDP$  डिफलेटर होगा -  $1,650 \div 1,100 = 1.50$  (या 150%)

### वास्तविक GDP (RGDP)

- मुद्रास्फीति-समायोजित GDP
- NGDP की तुलना में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन का अधिक सटीक प्रतिविवर
- 2 या अधिक वर्षों की GDP की तुलना करने के लिये उपयोग किया जाता है
- GDP मूल्य अवस्थितिकारक का उपयोग करके मापना की जाती है -  $(RGDP = NGDP + GDP \text{ अवस्थितिकारक})$



$d$  = मूल्यहास

$NFIA$  = विदेश से शुद्ध कारक आय

$NDP$  = सकल घरेलू उत्पाद

- कारक लागत (FC) =** किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले इनपुट का कुल मूल्य
- बाज़ार मूल्य (MP) =** कारक लागत + अप्रत्यक्ष कर - सम्बिडी
- FC पर GDP =** MP पर GDP + सम्बिडी - अप्रत्यक्ष कर
- MP पर GDP =**  $GVA \times MP$
- MP पर GDP भारत में GDP का माप है**
- सकल मूल्य वर्ट्टन (GVA) =**  $GDP + \text{उत्पादों पर सम्बिडी} - \text{उत्पादों पर कर}$



## ज़िला स्तरीय GDP अनुमान के कार्यान्वयन के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं?

- अनौपचारकि क्षेत्र:** **अनौपचारकि शरम** और असंगठित क्षेत्र पर अत्यधिक निभरता के कारण ज़िलों जैसी क्षेत्रीय इकाइयों को DDP अनुमान लगाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परणिमस्वरूप कम आकलन होता है।
  - इसके अतरिक्त, ज़िले की सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं और कारक भुगतानों के मुक्त आवागमन से सटीक आकलन करना और जटिल हो जाता है।
- वित्तीय और तार्ककि बाधाएँ:** ज़िला-स्तरीय GDP अनुमान के लिये एक सुदृढ़ सांख्यकीय ढाँचा स्थापित करने हेतु बुनियादी ढाँचे, प्रशक्तिशंक्षण और डिजिटल साधनों में महत्वपूरण नविश कायि जाने की आवश्यकता होती है।
- असंगत डेटा संग्रहण:** समवर्ती सूची के अंतर्गत सांख्यकीय केंद्र और राज्यों के बीच विखंडन उत्पन्न करती है, जबकि मिंत्रालयों में विकेंद्रीकृत सांख्यकीय प्रणाली में एकरूपता का अभाव है, जिससे **DDP अनुमान असंगत हो जाता है।**
  - मानकीकृत ज़िला-स्तरीय डेटा संग्रहण के अभाव के कारण राज्यों में अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं।

- मानकीकृत पद्धतिका अभाव: DDP का अनुमान लगाने के लिये **राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) 2008** जैसी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रूपरेखा नहीं है।
  - वभिन्न ज़िलों में आरथकि गतविधियों में भनिनता के कारण आधार वर्ष जैसे प्रमुख मानदंडों को परभिष्ठि करना चुनौतीपूरण है।
- राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएँ: राज्य उप-राज्य/DDP के संकलन के लिये ज़मिमेदार हैं, लेकनि प्रायः इसे प्रभावी ढंग से क्रयिन्वति करने में वफिल रहते हैं।
  - राज्य की नीतियों और राजनीतिक प्राथमिकताओं में भनिनता के कारण डेटा संग्रहण में वलिंबता और असंगतता होती है, जिससे DDP अनुमान की एकरूपता और वशिवसनीयता प्रभावित होती है।

## ज़िला स्तरीय GDP आकलन के क्या लाभ हैं?

- राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना: वकिंद्रीकृत आरथकि डेटा ज़िला प्रशासन को अनुकूलति रणनीति वकिसति करने में सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर संसाधन उपयोग और लक्ष्यति नविश सुनिश्चित होता है।
- सटीक आरथकि वशिलेषण: यह आकलन करने में सहायता करता है कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय नीतियों वभिन्न ज़िलों पर कसि प्रकार प्रभाव डालती है।
- समतामूलक वकिस: यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और अवकिसति ज़िलों को वकिस में शामलि कया जाए, जिससे आरथकि असमानताओं को कम कया जा सके।
- नीतिगत सुधार: **15 वें वत्ति आयोग** ने स्थानीय शासन के लिये प्रदर्शन-आधारति अनुदान की सफिरशि की है, ज़िला GDP डेटा इन संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने में मदद कर सकता है।
  - राज्य और राष्ट्रीय नीतियों को ज़िला स्तरीय आरथकि अंतरदृष्टि के आधार पर समायोजित कया जाना चाहयि।

## मज़बूत DDP आकलन के लिये आगे की राह क्या होना चाहयि?

- पायलट प्रोजेक्ट: सरकार **DDP आकलन मॉडल** का परीक्षण करने के लिये उच्च आरथकि गतविधिवाले ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत कर सकती है। सफल मॉडलों को अन्य ज़िलों में भी लागू कया जा सकता है।
  - ज़िला वज़िन दस्तावेज़ वकिसति करने के लिये राज्यों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मज़बूत करना, जैसा कि असम-पहल इंडिया फाउंडेशन MoU में देखा गया है।
- स्थानीय डेटा संग्रहण तंत्र: सरकार को ज़िला सांख्यकी कार्यालयों को मज़बूत करना चाहयि, स्थानीय डेटा संग्रहकरताओं को प्रशक्षिति करना चाहयि, और सटीकता के लिये मज़बूत कैंडेर-राज्य सहयोग सुनिश्चित करना चाहयि।
  - डेटा में प्रत्येक 1 अमेरकी डॉलर के नविश से 32 अमेरकी डॉलर का वकिस लाभ प्राप्त होता है, जो इसके दीर्घकालिक मूल्य को रेखांकति करता है।
- वास्तविक समय आरथकि संकेतक: GSMP और DDP अनुमान में सुधार के लिये उप-राष्ट्रीय लेखा समतिकी सफिरशि के साथ संरेखति करते हुए, रोजगार प्रवृत्ततयों, कर संग्रह, ऋण वृद्धि और व्यावसायकि गतविधिपर नज़र रखने के लिये ज़िला-स्तरीय आरथकि डैशबोर्ड वकिसति कया जा सकते हैं।
  - ज़िला स्तरीय आरथकि मापन में सुधार के लिये **आरटफिशियल इंटेलिंजेंस**, सेटेलाइट इमेजरी और बगि डेटा एनालिटिक्स जैसे डिजिटिल उपकरणों का लाभ उठाया जाना चाहयि।
- सांख्यकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भूमिका का वसितार: सांख्यकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की भूमिका को तकनीकी मार्गदरशन और क्षमता नरिमाण से आगे बढ़ाया जाना चाहयि, ताकि DDP आकलन में एकरूपता और अंतर-राज्यीय तुलनीयता सुनिश्चित की जा सके।

???????? ?????? ???????:

**प्रश्न:** भारत की वर्तमान GDP आकलन पद्धतिकी सीमाओं पर चर्चा कीजयि। बॉटम-अप दृष्टिकोण आरथकि नीतनरिमाण में कैसे सुधार कर सकता है?

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????????????????:

**प्रश्न.** स्फीतिदर में होने वाली तीव्र वृद्धिका आरोप्य कभी-कभी "आधार प्रभाव" (base effect) पर लगाया जाता है। यह "आधार प्रभाव" क्या है? (2011)

- यह फसलों के खराब होने से आपूरतमें उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है
- यह तीव्र आरथकि वकिस के कारण तेज़ी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है
- यह वगित वर्ष की कीमतों का स्फीतिदर की गणना पर आया प्रभाव है
- इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है

**उत्तर:** (c)

?????

प्रश्न. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2015 से पहले और वर्ष 2015 के पश्चात् परकिलन वथि में अंतर की व्याख्या कीजयि। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/district-level-gdp-estimation>

